www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-10* *October 2025***

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक बेहतर भविष्य का दर्पण

डॉ. अवधेश कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विष्वविद्यालय, दिल्ली

शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्यनतः, शिक्षा का संबंध लेखन और पुस्तकें पढ़ने से परिभाषित किया जाता है। लेकिन शिक्षा केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का अधिग्रहण शिक्षा का लक्ष्य है। ज्ञान मनुष्य को प्रकृति पर विजय पाने और मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करने में सहायता करता है। यह छात्रों और शिक्षकों की सामाजिक स्थिति को जोड़ता है। दुनिया के दार्शनिक और शिक्षक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। चूँकि शिक्षा कौशल और ज्ञान को बढ़ाती है। इन प्रकारों को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, सरकार या अधिकारी हमेशा इनके लिए नई नीति बनाने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस पेपर में, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या महत्व है? यह शिक्षक और छात्र दोनों के भविष्य के लिए कैसे बेहतर है?

नई शिक्षा नीति की जांच करने से पहले, हम शिक्षा के ऐतिहासिक महत्व के बारे में संक्षेप में जानेंगे। शिक्षा को पारंपरिक और व्यावसायिक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि पारंपरिक शिक्षा को कुछ विषयों के शिक्षण या पढ़ने के रूप में माना जाता है, उदाहरण के लिए, इतिहास, राजनीति विज्ञान, आदि, जबकि व्यावसायिक शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से भिन्न होती है। जबकि व्यावसायिक शिक्षा को कौशल विकास शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित होती है, उदाहरण के लिए, बीबीए, बीटेक, आदि शिक्षा जो व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है । इस प्रकार की शिक्षा को समय–समय पर अलग–अलग प्रकार की अवधि में जोड़ा जाता है। क्योंकि राज्य के अधिकारियों ने कभी–कभी छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ जोड़ीं जाती है। इसलिए, पिछली नीतियों से कई चीजें अपनाई गईं और कई चीजें हटायी गईं। जब हम नई शिक्षा नीतियों के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तब हमें पता चलता है कि आधुनिक शिक्षा नीति औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई थी। शिक्षा को सरकारी प्राथमिकता बनाने का पहला कदम 1813 का चार्टर एक्ट था। (ज़स्तौपिल, मौर 1999–90) शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अवधारणाएँ और नीतिगत विकल्प तथा कानून और विनियमन का समूह जो नियंत्रित करता है कि शैक्षिक प्रणाली कैसे चलाई जाती है, शिक्षा नीति बनाते हैं। आधुनिक सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। यह भी नियम बनाया कि 2009 में पारित शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्थानीय स्कूल में निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। (खेमका, कुमार 2019–40) चूँकि इस प्रकार की सुविधाएँ केवल सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित न रहे जिसके कारण सरकार ने निजी कॉलेजों के लिए भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नियम बनाए। इसलिए, अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपने 25% स्थान कम आर्थिक स्थिति वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए अलग रखने होंगे।

शिक्षा नीति के स्तर पर हालिया विकास को NEP 2020 के रूप में पेश किया गया था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख घटकों पर लोकसभा को जानकारी दी। सरकार ने समावेशी, न्यायसंगत, उच्च गुणवत्ता वाली और व्यापक शिक्षा प्रणाली की गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पेश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र में शैक्षिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और इसे अधिक बहु–विषयक और छात्र–केंद्रित बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य K–12 और उच्च शिक्षा में राष्ट्र के शैक्षिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तनों के द्वार खोलना है। हाल ही में शुरू की गई नई शिक्षा नीतियों के रूप में, सबसे पहले हम शिक्षा नीतियों के ऐतिहासिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यह जानेंगे कि शिक्षा नीतियां और मानवाधिकार

एक–दूसरे से कैसे जुड़े हैं।

भारत में शिक्षा नीति के विकास और ऐतिहासिक महत्व

भारत में शिक्षा का पहला दौर औपनिवेशिक काल में आया था। उसके बाद कई नीतियाँ शुरू की गईं। स्वतंत्रता के बाद बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा भी शुरू की गई। लेकिन यहाँ हम सभी नीतियों पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल कुछ महत्वपूर्ण नीतियों को ही विश्लेषण करेंगे जो कि इस पेपर के महत्वपूर्ण है । भारत सरकार ने 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ग्रामीण और शहरी भारत में निरक्षरता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई योजनाओं को पारित किया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के सभी पहलुओं पर राष्ट्रीय सरकार द्वारा कड़े नियंत्रण की कल्पना की थी। भारत की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949), (गावंडे. 2004, 12) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), (गावंडे. 2004, 13) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग (1961) की स्थापना की। शिक्षा नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए संघ और राज्य सरकारों को स्वतंत्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने 1961 में "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद" की स्थापना की। 1968 में, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया, जो कोठारी आयोग (1964–1966) के निष्कर्षों और सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति ने "आमूलचूल पुनर्गठन" का आह्वान किया और राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का सुझाव दिया।

राजीव गांधी के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। (निरंजनाराध्या 2004–45) नई नीति के अनुसार, 'असमानताओं को मिटाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि सभी छात्रों की शिक्षा तक पहुंच हो', विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी के लिए। पीवी नरसिम्हा राव प्रशासन ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में बदल दिया। (वत्स, त्रिपाठी 2002, 45) उनके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के 'सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम' प्रशासन ने एक नई रणनीति की नींव के रूप में कार्य किया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में अपनाया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) के अनुसार, 1992 के कार्य कार्यक्रम (पीओए) में देश भर में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना की गई थी इसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए। आवश्यक शिक्षण, आलोचनात्मक सोच और अधिक व्यापक अनुभवात्मक, चर्चा–आधारित और विश्लेषण–आधारित शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, इस बात पर चर्चा की गई है कि पाठ्यचर्या सामग्री में कैसे कटौती की जाए। इसमें छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर छात्र सीखने को अधिकतम करने के लिए 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को बदलने पर भी चर्चा की गई है। अगले भाग में हम कुछ विद्वानों को देखेंगे, जो NEP 2020 से पहले की शिक्षा नीतियों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि राहेल एल्बोइम ने अपने काम 'शिक्षा नीति निर्माण प्रणाली की कुछ विशेषताएँ' में जांच की है, शैक्षिक उद्देश्यों की अमूर्तता शैक्षिक प्रणाली कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसके औपचारिक उद्देश्यों में ठोस उद्देश्य शामिल हैं, जैसे पढ़ना, लिखना और गणित पढ़ाना, और अमूर्त उद्देश्य, जैसे प्रत्येक छात्र की क्षमता को अधिकतम करना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना पैदा करना।(वत्स, त्रिपाठी 2002, 232) शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वालों को निर्णय लेने के विश्लेषणात्मक तरीकों के प्रति उनके भावनात्मक प्रतिरोध को दूर करने में सहायता करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्हें यह दिखाना हो सकता है कि मूल्य निर्णयों की व्याख्या करना, विकल्पों की तलाश करना, उन विकल्पों का विश्लेषण करना और लागत–प्रभावशीलता के आलोक में उन विकल्पों का विश्लेषण करना किसी भी तरह से उनके मूल्य निर्णयों या उन उद्देश्यों से समझौता नहीं करता है जिन्हें वे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। (वत्स, त्रिपाठी 2002, 232) अरुण कुमार विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में इसका विश्लेषण करते हैं। (कुमार, 2015–14–16) जैसा कि उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलीन सेंट स्टीफंस कॉलेज में अपने संक्षिप्त प्रवास के बारे में एक लेख में, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्सचेंज छात्र रिचर्ड थाने ने इस तथ्य पर जोर दिया ...

वास्तविक शिक्षा वह है जो बुद्धि को चुनौती दे और प्रतिमानों पर सवाल उठाए, न कि याद करने और अनुरूपता की। भारत में विदेश में अध्ययन का मेरा पूरा अनुभव, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, एक बहुत बड़ी निराशा थी। ... फिर भी मेरे साथी भारतीय शिक्षा पूर्व छात्रों के बीच, जब कार्रवाई की बात आती है तो मैं ज्यादातर एक बहरापन सुनता हूं (2013)।

जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 20 वर्षों में उच्च शिक्षा में किए गए कई संशोधन शुरू में समझदारी भरे लग सकते हैं, लेकिन केवल अल्पावधि में। थोड़ा विचार करने पर पता चलेगा कि अंत में उनके विनाशकारी परिणाम होंगे। निजी क्षेत्र के नीति पर बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप अब अल्पावधि प्रमुख है। हालाँकि, व्यवसाय में सफलता यह सुनिश्चित नहीं करती है कि कोई छात्रों या शैक्षणिक संस्थानों की माँगों से अवगत है। उच्च शिक्षा दीर्घकालिक सामाजिक जिम्मेदारी

के बारे में है, चाहे तात्कालिक राजनीतिक और बाजार की माँगें कुछ भी हों। इस से जुड़े जंध्याला बी.जी. तिलक उच्च शिक्षा के संकट और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। (तिलक, 2015, 43–59) उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में संकट है। इस समस्या में वे विशेषताएं नहीं हैं, जिनका उल्लेख फिलिप कूम्ब्स (1968) ने 1960 के दशक में किया था या जे.पी. नाइक (1982) ने जिस "निरंतर संकट" को परिभाषित किया था। संख्या, अर्थशास्त्र, गुणवत्ता और महत्व ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो संकट को परिभाषित करते हैं। संक्षेप में, दक्षिण एशिया में प्रमुख विकासशील प्रतिमान को एक ऐसे प्रतिमान के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो उच्च शिक्षा को एक निजी वस्तु के रूप में देखता है। इस वस्तु का विपणन और व्यवसायीकरण किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर व्यापार और सीमा पार व्यापार शामिल हैं।

एनईपी 2019 नीति का विश्लेषण करने वाले काम हैं। जैसा कि "ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2019 पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया" (एआईएफआरटीइ, 2019, 3–26) ने नई शुरू की गई नीति के अलग–अलग पहलू दिए। भले ही यह परोपकार और "गैर–लाभकारी" संस्थानों की बात करता है, लेकिन ड्राफ्ट एनईपी 2019 शिक्षा के निजीकरण, व्यावसायीकरण और विपणन के नवउदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विदेशी कंपनियों के लिए विस्तारित शिक्षा बाजार में प्रवेश करना आसान बनाता है जिसका समर्थन यह "वैश्विक रूप से प्रासंगिक" ज्ञान के नाम पर करता है।

प्रधानमंत्री के अधीन भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति, 2005–2006.. यह सलाह दी जाती है कि समिति द्वारा रखी गई पुस्तकों, सार्वजनिक वक्तव्यों और अन्य सामग्रियों को नई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक पुस्तकालय में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि सरकार और आम जनता जब भी आवश्यक हो, उन तक पहुँच सकें।" (सच्चर रिपोर्ट, 2006)

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य अपने निर्णयों के बारे में वर्तमान शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक खुला था (जब इसने 1881–1883 में डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता वाले भारतीय शिक्षा आयोग को दी गई सभी टिप्पणियों और गवाही को प्रकाशित किया था)। इसलिए, हम इस पत्र को इस ईमानदार उम्मीद के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि सरकार, अगर वह वास्तव में चाहती है कि भारत एक अधिक समतावादी, न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण राष्ट्र बने– जरूरी नहीं कि एक महाशक्ति– तो वह अपने हाथों में पर्याप्त समय, वैकल्पिक विचारों के लिए खुलेपन और एक स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के ढांचे के भीतर लोगों के विचारों को अधिक लोकतांत्रिक तरीके से जानने का गंभीर प्रयास करेगी। नई शिक्षा नीति के प्रकाश में आने से पहले यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि यह मसौदा उत्तरार्द्ध का एक पक्ष है।

एम. अफ़ज़ल वानी ने शिक्षा को मानव के अधिकार के रूप में परखा है। (वानीः 1998, 243–62) उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि भारत में नीतियाँ कैसे लागू होती हैं. उन्होंने अपने तर्क का समर्थन इस तरह से किया कि यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के अर्ल वॉरेन, सी.जे. ने ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन में इस वास्तविकता पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके ज़ोर दिया–

"आज, राज्य और स्थानीय सरकारों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी शिक्षा हो सकती है. हमारे लिए अपने सबसे बुनियादी कर्तव्यों को पूरा करना ज़रूरी है.. . . ..अभी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो यह संभावना नहीं है कि वे जीवन में कुछ हासिल कर पाएँगे." (वानी– 1998–243–62)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, शिक्षा का महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण का नवउदारवादी तर्क, नए सार्वजनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन सुधार, और अन्य संस्थानों के समर्थन से एक नियामक प्राधिकरण की देखरेख में उच्च शिक्षा के लिए एक अर्ध बाजार का विकास, इन सभी ने वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा सुधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मुख्य नीतिगत परिवर्तन जो संप्रभुता के नाम पर उच्च शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देगा, वह है छात्रों द्वारा चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की सीमा को व्यापक बनाना। एनईपी ने सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए, यह एक संघीय प्रणाली में असंभव लगता है। हालांकि, सरकार उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के साथ–साथ एफडीआई और बाहरी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से विदेशों से अतिरिक्त वित्त के संचार के लिए नए रास्ते बना रही है। एनईपी, जवाबदेही प्रणालियों के निर्धारित तरीकों के कठोर पालन के अधीन प्रशिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करके राज्य–इंजीनियर बाजार में संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिस्पर्धा के निर्माण का संकेत देता है। एनईपी का उद्देश्य निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक प्रथाओं को हतोत्साहित करना है। सभी उच्च शिक्षा संस्थान इस भयंकर खेल में जीवित रहने में सफल नहीं होंगे। हालाँकि एसईडीजी के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की जानी है, लेकिन एनईपी अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नियमों के भविष्य के बारे में मौन है। उच्च

शिक्षा की अनूठी विशेषताओं को देखते हुए, न तो पारंपरिक अर्थों में एक बाजार और न ही ष्सार्वजनिकताष् को बढ़ावा देने वाला कोई ऐसा बाजार वांछित है, क्योंकि उच्च शिक्षा वैश्विक सार्वजनिक भलाई नहीं तो विश्वव्यापी लाभ के रूप में विकसित होती है। जैसा कि ऊपर के भाग में हमने शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं और उनकी समस्याओं को देखा है। इसने मानव जीवन और उनके भविष्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो, अगले भाग में हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 का क्या महत्व है।

एनईपी 2020 के महत्वपूर्ण कारक और छात्रों के लिए उनका लाभ

इस भाग में, हम नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण कारक की जाँच करने का प्रयास करेंगे। 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा और ज्ञ–12 शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में कई बदलाव करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई कार्य आइटम/गतिविधियाँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों में लागू किया जाना चाहिए। छम्ब् 2020 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं।

1. NEP 2020 की सहायता से, सरकार को उम्मीद है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होगी।
2. इस नई रणनीति के माध्यम से, लगभग दो करोड़ स्कूली छात्र शैक्षणिक संस्थानों में वापस आ सकेंगे।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, 5+3+3+4 संरचना वर्तमान 10+2 संरचना का स्थान लेगी। सीखने के प्रारंभिक वर्ष इस प्रणाली का मुख्य फोकस हैं। 3 से 18, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु को 5+3+3+3+4 संरचना द्वारा दर्शाया गया है। 12 वर्ष की औपचारिक शिक्षा, या 3 वर्ष यदि आंगनवाड़ी और प्रीस्कूल शामिल हैं।
4. एनसीईआरटी आठ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा में शिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और रूपरेखा तैयार करेगा।
5. शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति 2020 के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करना है। भारत के राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि तीसरी कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के पास पढ़ने और संख्यात्मकता में एक ठोस आधार हो। 2025 तक, यह कार्यान्वयन पूरा हो जाना चाहिए।
6. भारत में राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाना NEP 2020 के लाभों में से एक है।
7. उचित अधिकारी ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए स्कूल परीक्षणों का संचालन करेंगे। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं अभी भी दी जाएंगी, लेकिन एनईपी 2020 समग्र विकास पर जोर देने के लिए प्रणाली को फिर से डिजाइन करना चाहता है।
8. सरकार को परख के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए।
9. प्रत्येक भारतीय राज्य और जिले में "बाल भवन" नामक विशेष डे टाइम बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे। इस बोर्डिंग स्कूल का उपयोग खेल, पेशे और कलात्मक गतिविधियों में भागीदारी के लिए किया जाएगा।
10. राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति 2020 के अनुसार एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को सहेजा जा सकता है और छात्र की डिग्री पूरी होने की दिशा में गिना जा सकता है।
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देश भर में IIT और IIM के बराबर बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनका आयोजन बहु–विषयक शिक्षाविदों को पेश करने के लिए किया जाएगा।
12. एक ही मान्यता और नियंत्रण मानदंड सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संगठनों का मार्गदर्शन करेंगे।
13. कॉलेजों को स्वायत्तता दी जाएगी और कॉलेज कनेक्शन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।
14. शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए 2030 तक न्यूनतम चार वर्षीय बी.एड डिग्री की आवश्यकता होगी।
15. भविष्य में महामारी की परिस्थितियों के लिए छात्रों को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

जैसा कि ये पंद्रहवें बिंदु NEP2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि NEP किस तरह से छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, भारतीय उच्च शिक्षा के लिए अनिश्चित भविष्य15 छम्ब् की जांच करता है और सुझाव देता है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर में वृद्धि की गति को बनाए रखा जाना चाहिए और इसे 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% किया जाना चाहिए (NEP अनुभाग 10.8), लेकिन इसके स्वरूप में बदलाव के साथ। 2025 तक कम से कम 50%

छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से विस्तार में समान रूप से योगदान करने की उम्मीद है। कॉलेज संबद्धता को 15 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। 2030 तक, सभी शैक्षणिक संस्थानों को बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अनुसंधान को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जो अनुसंधान संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय की देखरेख भी करेगा। कोविड–19 के बाद शिक्षा को भी पुराने शिक्षण पद्धति के रूप में कुछ अपडेट की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी–मध्यस्थ शिक्षण के उद्भव और इंटरनेट एक्सेस में त्वरित प्रगति से उच्च शिक्षा उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव आने की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। महामारी के कारण शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण रुकावट के कारण प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेज़ी आई है। एनईपी ने व्यवधान के मौजूदा संकट से उबरने के लिए आवश्यक सभी बल और जुनून के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने को और बढ़ावा दिया है, लेकिन इनमें से अधिकांश सुधार विश्वविद्यालय के संचालन और वितरण संरचना में अंतर्निहित रहेंगे। ऑनलाइन निर्देश मौलिक रूप से पारंपरिक ष्इन–क्लासष निर्देश को बदल देता है। कुछ शिक्षाविदों की ओर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन शिक्षण प्रतिरोध वर्तमान परिवेश में अब प्रासंगिक नहीं है। समय और स्थान, जो 'इन–क्लास' ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं, ऑनलाइन सीखने में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। जबकि पारंपरिक कक्षा निर्देश एक सेवा का उदाहरण है, ऑनलाइन निर्देश, यदि डिजिटलीकृत और रिकॉर्ड किया जाता है, तो 'इन–क्लास' निर्देश को एक डिजिटल उत्पाद में बदल देता है जो एक दिन दुनिया में किसी के लिए भी सुलभ हो सकता है, निश्चित रूप से, शिक्षक या संस्थान के विवेक के अधीन। यदि हम NEP की सिफारिशों का पालन करते हैं, तो HEI अपने स्वयं के मार्ग चुनने और जीवन–या–मृत्यु की स्थिति में गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो शिक्षकों और संस्थानों को दी जाने वाली स्वायत्तता के कारण होगा। विकल्प प्रदान करके दी गई संप्रभुता के कारण भारतीय बाजार में कुछ शीर्ष रैंक वाले अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों के संभावित प्रवेश के साथ बाजार और भी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। भले ही यह माना जाता है कि ऑनलाइन निर्देश की औसत लागत आम तौर पर कम होती है, जिसमें प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र को जोड़ने की सीमांत लागत न्यूनतम होती है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है यदि ऑनलाइन निर्देश की सीमाओं से निपटने के लिए छात्रों को विशेष सहायता देने के लिए खर्च किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की भागीदारी कुछ ऐसी चीज रही है जिससे नीति निर्माताओं को संघर्ष करना पड़ा है। हालाँकि DNEP इस मामले पर चुप था, लेकिन NEP ने एक बार फिर इस विवादास्पद विषय को उठाया है। उच्च शिक्षा में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) को मंजूरी देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करना पहले से ही 2020–21 के केंद्रीय बजट भाषण में शामिल किया गया है ताकि भ्म् द्वारा प्रत्याशित क्षमता निर्माण को निधि देने के लिए संसाधनों का प्रवाह सक्षम हो सके। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) या टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) रैंकिंग के अनुसार, NEP भारतीय बाजार में प्रवेश को केवल शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों तक सीमित रखना चाहता है। इस अर्थ में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कॉलेज सेल फोन कारखानों के समान काम नहीं करते हैं, जहां एक नव स्थापित कारखाने द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता दुनिया भर में स्थित अन्य मौजूदा कारखानों द्वारा उत्पादित गुणवत्ता के समान ही होगी।

ऑनलाइन निर्देश के माध्यम से बेहतरीन विश्वविद्यालयों द्वारा क्षमता विकास की संभावना के कारण, संभवतः दो बाजार खंड होंगे, एक प्रमाणित और मान्यता प्राप्त के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला और दूसरा शेष द्वारा आबाद। नई तकनीक के दीर्घकालिक प्रभावों पर अटकलें लगाते हुए, बोक ने 2013 में लिखा (पृष्ठ 148)–

"कुछ टिप्पणीकार एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें कुछ प्रसिद्ध प्रशिक्षकों का वर्चस्व हो जो इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों को पढ़ाते हैं, जबकि हजारों प्रोफेसरों को अनावश्यक रूप से छोड़ दिया जाता है जो लगातार बढ़ते छात्र दर्शकों को अपने व्याख्यान देते रहते हैं।"

इस वजह से, जैसे–जैसे उच्च शिक्षा क्षेत्र अधिक विशिष्ट होता जाएगा, नौकरी के बाजार में डिग्री का मूल्य अलग–अलग होगा। समय के साथ, NAC बाइनरी ग्रेडिंग में बदल जाएगा, जो खराब प्रदर्शन करने वाले भ्म् को बाहर कर देगा। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाना,16 NEP 2020 से पहले, भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई शैक्षिक तकनीक के रूप में बैकलॉग के पारंपरिक प्रभावों से काफी नुकसान हुआ। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, कोई भी आयातित संरचना वांछित परिणामों को जन्म नहीं दे सकती है। भारत को शिक्षक शिक्षा के लिए एक व्यावहारिक और जमीनी शैक्षिक प्रणाली पर जोर देना चाहिए जो समकालीन अनुसंधान के साथ पारंपरिक भारतीय मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हाल ही में हुए बदलाव इन सुधारों के उदाहरण के रूप में काम करते हैं। इसलिए, महत्वपूर्ण मॉडल अपने अंतर्निहित लाभों के बावजूद भारतीय संदर्भ में दुर्गम नहीं हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक शोध के साथ मिलाने से शैक्षिक गुणवत्ता में एक बुद्धिमान सुधार हो सकता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए विनियम– NEP 2020 यह निर्धारित करता है कि वर्तमान ज्म् को 2030 तक 4–वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) शुरू करने और पेश करने के लिए

विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। 2030 तक, जब ITEP लागू होगा, तो योग्यता की न्यूनतम डिग्री अभी भी एक बाधा होगी इससे शोध को लाभ होगा, लेकिन शिक्षक शिक्षा को इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के साथ–साथ भारत और इसके मूल्यों, लोकाचार, कला और परंपराओं की समझ के साथ–साथ अन्य चीजों की गहरी समझ से भी लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली बनाने पर केंद्रित है, जो सभी को उच्च–गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके एक निष्पक्ष और संपन्न ज्ञान समाज बनाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, यह शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने और आज के प्रशिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने पर जोर देता है। एक नया चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी. बी.एड. एनसीटीई ने समर्पित, जिम्मेदार और पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने के लिए एनईपी 2020 की सिफारिश पर कार्यक्रम विकसित किया। ज्ञान के उदार विषयों और शिक्षा के क्षेत्र के साथ चल रही बैठकों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के शिक्षण और विषय–वस्तु के आवश्यक पार्श्व विलय की योजना बनाई गई थी। शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों के लिए, NEP 2020 ने नवाचार और मानक–निर्धारण विनियमों की स्थापना की कल्पना की।

निष्कर्ष

29 जुलाई, 2020 को सरकार ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों में ड्रॉपआउट की संख्या कम होगीः विशेष शिक्षा क्षेत्रों के निर्माण, लिंग समावेशन कोष की स्थापना और खुले और दूरस्थ शिक्षा विकल्पों तक पहुँच में वृद्धि के कारण, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों के पास अधिक विकल्प होंगे, जो NEP 2020 के प्रभाव के हिस्से के रूप में ड्रॉपआउट की संख्या को कम करेगा। 2030 तक, NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को व्यापक रूप से सुलभ बनाना है। भारत में शिक्षा की उन्नति के लिए दृष्टि और पाठ्यक्रम को समझाने वाला एक संपूर्ण दस्तावेज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 है। यह इक्कीसवीं सदी की माँगों और आकांक्षाओं के लिए शैक्षिक प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना चाहता है। चाहे उनकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, सभी लोगों को उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच की आवश्यकता होती है, और NEP 2020 शिक्षा में समावेशिता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर देता है। यह बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देता है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सुनिश्चित करता है और छात्रों की आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। NEP 2020 रटने की शिक्षा से दूर जाने और अधिक व्यापक और बहु–विषयक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने पर जोर देता है। यह समस्या–समाधान क्षमताओं, आलोचनात्मक सोच और अनुभव सीखने को बढ़ावा देता है– ये सभी बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को उपयोगी कौशल देने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए, नीति व्यावसायिक शिक्षा के मूल्य को भी स्वीकार करती है और इसे मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करती है। NEP 2020 कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह शिक्षण और सीखने को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण वातावरण को शामिल करने को प्रोत्साहित करता है NEP 2020 का शिक्षक तैयारी और व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना एक और महत्वपूर्ण घटक है। रणनीति शिक्षकों को उनकी शिक्षण क्षमताओं और ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहायता और प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है क्योंकि यह स्वीकार करती है कि वे भविष्य में शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। NEP 2020 एक मजबूत मूल्यांकन संरचना विकसित करने का भी आह्वान करता है जो पारंपरिक परीक्षणों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय छात्रों के कौशल और क्षमताओं के गहन मूल्यांकन पर जोर देता है। योग्यता–आधारित मूल्यांकन प्रणाली में यह परिवर्तन छात्रों के तनाव और चिंता को कम करने और उनकी समग्र योग्यता की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, NEP 2020 शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने और संगठन को बहु–विषयक पाठ्यक्रमों के प्रदाता में बदलने पर जोर देता है। जल्द ही, NEP 2020 को भारत की शैक्षिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पहचाना जाएगा।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is

no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

References

1. All India Forum for Right to Education (AIFRTE). "Critical Response to the Draft National Education Policy, 2019." Social Scientist 47, no. 9/10 (556-557) (2019): 3–26. https:// www.jstor.org/stable/26844282.
2. All India Forum for Right to Education (AIFRTE). "Critical Response to the Draft National Education Policy, 2019." Social Scientist 47, no. 9/10 (556-557) (2019): 3–26. https:// www.jstor.org/stable/26844282.
3. Appendix , Indian Journal of Research, Volume 11 , Issue 02 , 2 , Print ISBN 978-1-85966-573-9 No. 2250 , 1991
4. Dryden-Peterson, S. (2016). Refugee Education: The Crossroads of Globalization. Educational Researcher, 45(9), 473–482. http://www.jstor.org/stable/44971844
5. Excerpted from Justice Sachhar's conveyance letter dated 17 November 2006 to the Prime Minister
6. Gawande , E. N., (2004). Value Oriented Education. India: Sarup Book Publishers Pvt. Limited.
7. Hollowell, A., & Payne, N. J. (2022). COVID-19, Higher Education, and Social Inequality. In G. L. Wright, L. Hubbard, & W. A. Darity (Eds.), The Pandemic Divide: How COVID Increased Inequality in America (pp. 256–275). Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv2vr9d90.15
8. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
9. Kumari, A., & Sharma, P. (2021). Social Responsibility and Legal Education in India: A Study in Special Reference to National Law Universities. In B. Hall & R. Tandon (Eds.), Socially Responsible Higher Education: International Perspectives on Knowledge Democracy (pp. 153–168). Brill. http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbn5.19
10. Kumar, Arun. (2015). "Challenges Facing New Education Policy in India." Economic and Political Weekly 50, no. 52: 14–16. http://www.jstor.org/stable/44003016.
11. Lynn Zastoupil, Martin Moir (ed.) (1999). The Great Indian Education Debate: Documents Related to the Orientalist- Anglicist Controversy, 1781-1843. United Kingdom: Curzon.
12. Mitra, N. L. (2020). An Introductory Note: National Policy on Higher Eduction. Journal of the Indian Law Institute, 62(4), 390–412. https://www.jstor.org/stable/27296725
13. National Education Policy 2020. (2021). World Affairs: The Journal of International Issues, 25(4), 138–168. https://www.jstor.org/stable/48654887
14. Niranjanaradhya, V. P. (2004). Universalisation of School Education: The Road Ahead—. India: Centre for Child and the Law, National Law School of Indian University.
15. Nitya Mohan Khemka, Suraj Kumar (ed.), (2019). Social Development and the Sustainable Development Goals in South Asia. United Kingdom: Taylor & Francis.
16. Saumen Chattopadhyay (schatto@gmail . com) teaches at the Zakir Hussain Centre for Educational Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
17. Tilak, Jandhyala BG (2015). "Higher Education in South Asia: Crisis and Challenges." Social Scientist 43, no. 1/2: 43–59. http://www.jstor.org/stable/24372963.
18. Vatsa, Dr Ghanshyam (2022). Gireesh Tripathi, Priyanka Malhotra, Ms. Kshitija Landge , Human Rights Education: A.G. Publication House.

Cite this Article

'डॉ. अवधेश कुमार सिंह', "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक बेहतर भविष्य का दर्पण', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10, October 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i1000016

Published Date- 05 October 2025